रहेंगा, तब तक ...(**व्यवधान**)...तो उनको ऊपर

बिहार में कम्प्यूटर शिक्षा

*182 डा. कुभकुम रायः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के केन्द्रीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु राज्य को आवंटित की गई धनराशि का उस अवधि के दौरान उपयोग किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री (डा. [श्रीमती) रीता वर्मा]: (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बिहार में स्थित निम्नलिखित विद्यालयों को कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कुल 1,33,40,500/- रुपए की राशि आवंटित की थीः-

1	केन्द्रीय विद्यालय न. 1 गया।	13,69,500/-रु.
2	केन्द्रीय विद्यालय न. 2 गया ।	9,38,000/- रु.
3	केन्द्रीय विद्यालय जमालपुर	9,38,000/-रु.
4	केन्द्रीय विद्यालय सिंगरशी	9,38,000/-रु.
5	केन्द्रीय विद्यालय समस्तीपुर	15,00,000 /-रु.
6	केन्द्रीय विद्यालय मोकामाघाट	9,38,000 / रु.
7	केन्द्रीय विद्यालय मुज्जफ़रपुर	15,00,000/रु.
8	केन्द्रीय विद्यालय सोनपुर	9,38,000 / रु.
9	केन्द्रीय विद्यालय कटिहार	9,38,000 / रु.
10	केन्द्रीय विद्यालय गरहरा	9,38,000 / रु.
11	केन्द्रीय विद्यालय कंकड़बाग, पटना	14,67,000 / रु.
12	केन्द्रीय विद्यालय बेली रोड, पटना	9,38,000 / रु.

जिन 12 विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा हेतु निधियां संस्वीकृत की गई थी,उनमें से 10

विद्यालयों में राशि का पूर्ण उपयोग किया गया है। दो केन्द्रीय विद्यालयों अर्थात् केन्द्रीय विद्यालय जमालपुर और केन्द्रीय विद्यालय सिंगरशी में कार्य, संस्वीकृत राशि की तुलना में, काफ़ी कम राशि में ही पूरा कर लिया गया था।

जहां तक कॉलेजों का संबंध है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 38 कालेजों को कम्प्यूटर शिक्षा के प्रचार –प्रसार के लिए 48,34,196 / रुपए की राशि संस्वीकृत की है। 10,29,196/-रुपए की राशि वर्ष 1999-2000 में तथा 6,60,000/- रुपए की राशि 2000-2001 में संस्वीकृत की गई थी। 4,94,96/- रुपए की राशि के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं। इन 38 कालेजों में से 23 कालेजों को मार्च, 2002 में 25,30,000/-रुपए की सहायता दी गई थी। इस राशि का उपयोग एक वर्ष के भीतर किया जाना है।

Computer education in Bihar

† *182. SHRIMATI KUM KUM RAI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of funds allocated by Government for dissemination of computer education in Central Schools and Colleges of Bihar during the last three years;

(b) whether the funds allocated to the State for this purpose have been utilized during that period;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT [DR. (SHRIMATI) RITA VERMA]: (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (d) During the last three years a total sum of Rs.1,33,40,500/-was allocated by the Kendriya Vidyalaya Sangathan to the following schools in Bihar for computer education.

1.	KVNo. 1 Gaya	Rs. 13,69,500/-
2.	KV No. 2 Gaya	Rs. 9,38,000/-
3.	KVJamalpur	Rs. 9,38,000/-

† Original notice of the Question was received in Hindi.

4.	KV Singarshi		Rs. 9,38,000/-
5.	KV Samstipur		Rs. 15,00,000/-
6.	KV Mokamaghat		Rs. 9,38,000/-
7.	KV Muzaffarpur		Rs. 15,00,000/-
8.	KV Sonepur		Rs. 9,38,000/-
9.	KV Kathihar		Rs. 9,38,000/-
10.	KV Garhara		Rs. 9,38,000/-
11.	KV Kankarbagh,	Patna	Rs. 14,67,000/-
12.	KV Bailey Road,	Patna	Rs. 9,38,000/-

Out of the 12 schools for which funds were sanctioned for computer education, the amounts have been fully utilized in 10 schools. In two schools, namely KV Jamalpur and KV Singarshi, the work was completed in substantially less than the sanctioned amount.

As far as college are concerned, the University Grants Commission (UGC) has sanctioned a total amount of Rs. 48,34,196/-to 38 colleges in the last three years for dissemination of computer education. An amount of Rs.10,29,196/- was sanctioned in the year 1999-2000 and Rs. 6,60,000/- in 2000-2001. Utilisation Certificates have been received for an amount of Rs.4,94,196/-. Out of the 38 colleges, 23 colleges were given assistance amounting to Rs. 25,30,000/- in March, 2002.This amount is meant for utilisation within a year.

डा. कुमकुम राय: सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में जो संख्या मुझे मिली है और मैंने जो ब्यौरा मांगा था, वह ब्यौरा भी अधूरा है। 12 केन्द्रीय विद्यालयों में यह राशि केन्द्र सरकार ने भेजी है। इसके साथ ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने जो संशोधन योजना बनाई थी, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में एक स्कूल को स्मॉर्ट स्कूल बनाया जाएगा और उसको अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वह अपने पड़ोस के दस स्कूलों को कमप्यूटर साक्षरता अध्ययन प्रदान करने के लिए, आस-पास के तमाम जो स्कूली बच्चे हैं, उनको लाभान्वित करेंगे, तो पहले ही यह कमी मेरे खंड "क" के उत्तर में ही है कि 12 स्कूलों में कौन –सा स्मॉर्ट स्कूल हैं और इसमें अपने पड़ोस के कौन से दस स्कूलों को जोड़ा है, वे दस स्कूल क्या सरकारी स्कूल होने अनिवार्य है, तो न वह स्मार्ट स्कूल का नाम है, न ही पड़ोसी दस स्कूलों के नाम हैं और न ही बताया गया है कि वह स्मार्ट उन दस पड़ोसी स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा किस माध्यम से देगा और वे पड़ोसी स्कूल के बच्चे क्या इस कंप्यूटर साक्षरता को प्राप्त करने के लिए क्या कोई शुल्क अदा करेंगे या नहीं। यह तो खंड "क" का ही अधूरा उत्तर है। इसके बाद जो निचला पोर्शन है महाविद्यालय के लिए यू.जी.सी. के जो अनुदान की बात

कही गई हैं उसमें भी अधूरी जानकारी है। किसी विश्वविद्यालय के कौन से महाविद्यालय में कितनी राशि दी गई है, यह उत्तर में है ही नहीं। इसलिए महोदय, पहले मुझे पूर्ण उत्तर दे दिया जाए तब में सप्लीमेंटरी करुंगी।

डा. (श्रीमती) रीता वर्मा: महोदय, हमारी सरकार ने और पहले की सरकारों ने भी आज के युग में शिक्षा में कम्प्यूटर की अनिवार्यता को अनुभव किया था और इसके लिए योजनाएं बनाई थीं। साथ ही जब से डा. जोशी साहब ने मानव संसाधन विकास विभाग का कार्यभार संभाला, उन्होने कम्प्युटर शिक्षा के प्रचार-प्रचार में बहुत ज्यादा रुचि ली है और इस के लिए कई योजनाएं चल रही हैं और मुझे लगता है इसी बात को लेकर कुछ कनफ़्यूजन हो रहा है। महोदय, यह जो प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के किस-किस केन्द्रीय विद्यालय में कमप्यूटर शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार द्वारा निधि आवंटित की गयी है, तो बिहार में 26 केन्द्रीय विद्यालय है और सभी में कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। इन विद्यालयों में से 12 को सीधे पैसा दिया गया है और 6 ने अपने विद्यालय विकास निधि से पैसे लेकर कम्प्यूटर खरीदे हैं और कम्प्यूटर शिक्षा का इंतजाम किया है। बाकि को भी दूसरी तरह से सहायता दी गयी है। वे दूसरी एजेंसियों से सहायता लेकर कम्प्यूटर शिक्षा दे रहे हैं। दूसरे आपने स्मार्ट स्कूल योजना के बारे में पूछा है, इसमें हर राज्य में एक केन्द्रीय विद्यालय और एक नवोदय विद्यालय को लिया जाएगा। महोदय, यह एक नई स्कीम है और अभी इम्पलीमेंटेशन की स्टेज में है। उस के लिए अभी स्कूलों का चुनाव नहीं हुआ है और उस के लिए प्रपोजल मांगे जा रहे हैं। मुझे सदन को बताने हुए हर्ष हो रहा है कि जो स्मार्ट स्कूल बनेंगे, उन को 25-25 लाख रुपए दिए जांएगे ताकि बच्चे बचपन से ही कम्प्युटर के प्रयोग मै निष्णात हो सकें और 15-15 हजार रुपये अगल-बगल के स्कूलों के लिए होगें जहां कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा नहीं है। ऎसे स्कूलों को एडाप्ट करके वे कम्प्यूटर की शिक्षा देंगे। इस के लिए प्रत्येक स्कूल को डेढ़ लाख रुपए अलग से देने का प्रावधान किया गया है, पर अभी उन स्कूलों के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इसलिए मैं अभी नहीं बता संकूगी कि बिहार के बिहार के किस केन्द्रीय विद्यालय को इस योजना के लिए चुना गया है । महोदय, मुझे उम्मीद है कि इस सब जानकारी से माननीय सदस्या को बहुत संतोष हुआ होगा। जहां तक कॉलेजज की बात है, महोदय कॉलेजज की लिस्ट मेरे पास है। यदि सदन चाहे तो मैं वह पूरी लिस्ट पढ़ सकती हूँ।

श्री लालू प्रसाद: आप उसे नहीं पढ़िए क्योंकि उसमें समय बर्बाद होगा।

श्री सभापति: आप उसे सदन के पटल पर रख दीजिए।

डा. (श्रीमती) रीता वर्मा: सर, आप कहते हैं तो मैं उसे सदन के पटल पर रख देती हूँ। इसमें यह सारी लिस्ट दी गई है। इन में से कुछ कॉलेजज को पिछले तीन सालों में दो बार पैसे दिए गए है। पहले, वर्ष 1994 में उन को पैसा दिया गया है और 6 कालेजज हैंजिन को दोबारा अपग्रेडेशन के

लिए भी पैसा दिया गया है क्योंकि उन्होंने वह राशि खर्च कर ली थी, परंतु मै माननीय सदन के नोटिस में यह बात भी लाना चाहूंगी कि उन में कई कॉलेजज ऐसे हैं जिनसे कि हिसाब –किताब नहीं आया है और जब तक हिसाब-किताब नहीं आता है तब तक हम दूसरी राशि न अपग्रेडेशन के लिए और न दूसरे किसी काम के लिए मुहैया कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करुंगी कि वह इस विषय में रुचि लेकर कृपया हमें खर्च का विवरण भिजवा दें और चूंकि कम्प्यूटर टैक्नोलोजी हर दो-तीन साल में बदलती रहती है....

डा. कुमकुम राय: इसीलिए लिस्ट मांगी है।

डा. (श्रीमती) रीता वर्मा: मैं लिस्ट पढ़ देती हूँ।

श्री सभापति: लिस्ट पढने की जरुरत नहीं है, आप उसे माननीय सदस्य को भिजवा दीजिए।

डा. (श्रीमती) रीता वर्मा: जी, मैं भेज दूंगी।

डा. कुमकुम राय: सभापति महोदय, मेरा दूसरा पूरक यह प्रश्न है। सन् 2001 और 2002 में स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता अध्य्यन की संसोधित योजना के तहत राज्यों द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं के आधार पर केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और राज्य सरकार 25 प्रतिशत निधि प्रदान करेगी। बिहार जैसे निर्धनतम् राज्य के पास जहां सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को भी समय पर वेतन देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं और वह हर साल बाढ़ व सुखाड़ से त्रस्त रहता है। जिससे कि उस का अपना बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्कर ही खत्म हो जाता है महोदय, बिहार राज्य बांट दिया गया, लेकिन उस के लिए कोई विशेष कार्यक्रम भी नहीं बनाया गया? तो क्या माननीय मंत्री महोदया बिहार के इन स्कूलों में पढने वाले गरीब बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष योजना के तहत 25 प्रतिशत निधि को शामिल करते हुए बिहार राज्य को यह राशि प्रदान करने का विचार रखती है?

डा. (श्रीमती) रीता वर्मा: सभापति जी, मैं पूरी विनम्रता के साथ यह कहना चाहूंगी विद्या प्राप्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो उसके लिए इच्छा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और दूसरा उसके लिए धनराशि होनी चाहिए। जहां तक राशि का सवाल है, हम अपनी तरफ़ से, जो भी फ़्लांनिंग कमीशन के नॉर्मस हैं, उसको पूरा करने के लिए तैयार है यह नार्मस हम अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, यह हमारे हाथ में नहीं है यह योजना ही बनी थी...(**व्यवधान**).... प्लीज, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। यह योजना बनी थी कि 75 प्रतिशत केन्द्र देगा और 25 प्रतिशत राज्य की तरफ़ से मिलेगा। अब इसमें यदि किसी राज्य के लिए एक सिस्टम होगा, तो उस पर काफ़ी बड़े स्तर पर विचार –विमर्श होना चाहिए। दूसरी बात है इच्छा का

होना, तो मैं सम्मानित सदस्या के ध्यान में यह लाना चाहूंगी, शायद उनके ध्यान में नहीं है, और भी वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हुए हैं, कि हमारे विभाग की ओर से चिटिठयाँ पर चिटिठयाँ **गइ है कि आप कम्प्युटर शिक्षा प्रकार योजना बनाकर भेजिए । अभि तक यह चार** चिटिठयाँ जा चुकी हैं, मैं आपको डेट बता देती हूँ, एक चिटठी गई है 3-12-2001 को, दूसरी 21-12-2001 को, तीसरी चिटठी गई है। 15-01-2002 को और फ़िर इसके बाद 25-02-2002 को गई हैं, परन्तु दुर्भाग्य की बात कि आज तक किसी भी चिटठी का जवाब नहीं आया, कोई योजना बनाकर नहीं भेजी गई। अब राज्य योजना बनाकर नहीं भेजेगा,हमने तो सीईपी बना दी है कि कम्प्यूटर एजुकेशन प्रोजेक्ट आप भेजिए हम पैसा देंगे, परन्तु योजना ही नहीं आएगी तो हम कैसे मदद कर सकते हैं। यह हमारी दिक्कत है, महोदय।

श्री मुरली सीताराम देवरा: सभापति जी, बिहार की ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान की बात है सम्मानीय मंत्री महोदया ने कहा कि विद्या प्राप्ति के लिए लगन की जरुरत है, लेकिन साधन की भी बडी जरुरत होती है, खासकर कमप्यूटर शिक्षा देने के लिए बहुत बड़े साधनों की जरुरत है भारतवर्ष में एक ऐसी स्कीम चली है, जिसके अनुसार हजारों गरीब बच्चों को स्कूलों में फ़्री कमप्यूटर शिक्षा, जैसे भारतीय विद्या भवन देती है,वह दे सकते है। उसमें सबसे बडी समस्या क्या है? सबसे बडी समस्या यह है कि एनजीओस को बाहर से, विदेशों से जो लोग फ़ेरस्ड-आऊट कमप्यूटर डोनेट करना चाहते हैं, हजारों कमप्यूटर डोनेट करना चाहते है अमेरिका और दूसरे देशों में, उनको हमारे देश में इम्पोर्ट नहीं होने दिया जा रहा । क्यों नहीं होने दिया जा रहा? इसलिए कि इसमें बडी मात्रा में इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप वित्त मंत्रालय से इस इश्यू को उठाएंगे कि जिन स्कूलों में गरीबों को फ़्री, मुक्त कम्प्यूटर शिक्षा दी जाए, उन्हें फ़ेरस्ड-आऊट कम्प्यूटर बिना ड्यूटी के इम्पोर्ट करने दिया जाए?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): श्रीमन् सम्मानित सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि वित्त विभाग की ओर से पहले ही ज्ञापन जारी हो चुका है और यह सुविधा है कि ऐसे मामलों में कोई तटकर नहीं लगता, लेकिन मुझे दूसरी बात कहनी है और वह यह है कि हमे आज इस बात की जरुरत नहीं है कि हमे विदेशों से चीजें डोनेट होकर मिलें। हमारे देश में भी आज ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जिनके अनुसार हम कम्प्यूटर **शिक्षा को बहुत कम खर्च मे और अनेक स्थानों पर हमारे ही देश मै जो कम्पुटर** उपलब्ध हैं वह देकर कर सकते हैं। जहां से ऐसी मांग आती है या जो राज्य सरकारें ऐसी योजनाएं बनाती हैं, हम उनको पूरी मदद करते हैं और हमने उनको पूरी सुविधा दी है। आपको जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि आज यह व्यवस्था की हुई है कि अगर किसी विद्यालय में कोई एनजीओ या कोई ऐसी संस्था कम्प्यूटर शिक्षा देना चाहे तो उस विद्यालय के अंदर हम उनको रखने के लिए स्थान देते हैं। कम्प्यूटर वह अपने लाते हैं तो वह देते हैं, नहीं तो हम भी थोड़ा इंतजाम करके देते हैं। केवल मेंटीनेन्स के ऊपर वह हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं और बाकी

अपना काम बाहर के जो संपन्न लोग हैं उनको शिक्षा देकर वह कर सकते हैं। हमने यह भी स्कीम चलाई है। इसके अलावा विदेशों से जिस तरह के कम्प्यूटर आते हैं उसी स्तर के कम्प्यूटर हम भी देने को तैयार हैं। ....(**व्यवधान**)... हां साहब बहुत बड़ी मात्रा मे हम देते है कोइ चिंता की बात नही है हम यहां षें आन्य विदेशो को भि दे हैं है। हमे कोए चिंता नही है।....(**व्यवधान**)...

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया: मंत्री जी, एक सेकेण्ड।

डा. मुरली मनोहर जोशी: कृपा करके मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आज इस बात को समझने की जरुरत है, यह धारणा बदलने की आवश्यकता है कि जब एनजीओस को विदेशों की मार्फ़त से या एनआरआईस की मार्फ़त से कम्प्यूटर आएंगे तभी हम बहुत शिक्षा दे पाएंगे। हमें आज इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है। हमारे पास जहां से योजनाएं आती हैं, हम उनकी पुरे तौर से **कम्पुटर की सहायता कर रहे है,** हैं। और अभी जैसा मैंने बताया कि हम अन्य देशों को भी अपने यहां से इसी प्रकार से मदद करते हैं। हाल ही में मंगोलिया से हमने एक ऐसा करार किया है जिसमें हम वहां स्कूल में कम्प्यूटर भी देंगे, अध्यापक भी देंगे। इसलिए इस धारणा को बदलने की जरुरत है कि जब विदेशों से या एनजीओस या एनआरआईज के मार्फ़त से कम्प्यूटर आएंगे, तभी हम बहुत लोगों को शिक्षा दे सकेंगे। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ कि बाहर से हमारे पास अच्छी चीजें न आएं, अच्छी चीजें आएं, जरुर लेंगे लेकिन बहुत पुराने कम्प्यूटर लेने से हमारा काम नहीं चलता ....(**व्यवधान**)....

श्री मुरली सीताराम देवरा: क्राइटेरिया के बारे में .....(**व्यवधान**)....

डा. मुरली मनोहर जोशी: वही करते हैं और उसके लिए पूरे तौर पर तटकर की निवृत्ति की जा चुकी है , वे सरकुलेशंस हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

SHRI MURLI DEORA: I do not want to challenge the statement of the Minister. But, according to my information, which is as late as last week, there is no blanket order by the Finance Ministry, which allows duty-free import for NGOs. Only case-by-case import is allowed. जोशी साहब, आप मेहरबानी करके चैक कर लिजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी: केसे-बाई-केस तो होगा ही।

श्री मुरली सीताराम देवरा:अभी 6 महीने और लगेंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी: नहीं लगेंगे। अगर ठीक समय पर आए और हमारे विभाग के पास जानकारी आ जाए तो हम बहुत जल्दी उसको साफ़ करेंगे क्योंकि आज देश में जैसी सुरक्षा की स्थिति है और सारी चीजें हैं, उसमें यह आवश्यक है कि इन मामलो में हमें केस-बाई-केस बहुत

बारीकी से छान-बीन करके देना चाहिए। उसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे।

श्रीमती सविता शारदा: सभापति महोदय, जैसा कि कम्प्यूटर शिक्षा के प्रचार-प्रसार की नीति की बात हो रही है। अभी इसे 10वीं कक्षा में कम्पलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है, इसे बच्चों को पढना जरूरी है, जैसे पहले टाइपिंग वगैरह होता था, उसी प्रकार यह कम्प्यूटर एक कम्पलसरी सब्जेक्ट हो गया है। गुजरात में ऐसे बहुत से आदिजाति या आदिवासी एरिया हैं, जहां पर अभी तक कम्प्यूटर पहुंचा ही नहीं है मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि गुजरात में ऐसे कितने स्कूल कालेज हैं और उनको कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

डा. (श्रीमती) रीता वर्मा: महोदय, गुजरात को अभी तक क्लास-3 में जो पैसे दिए गए हैं , वे 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उसमें से 7.5 करोड़ रुपए रिलीज हो चुके हैं 300 स्कूलों के लिए। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि यह जो कम्प्यूटर एजुकेशन प्लान मानते हैं, यह एक डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट है और आगे भी जैसे-जैसे स्कूलों से उनकी रिक्वेस्ट या रिक्विजीशन आती जाएंगी, हम उनकी पूर्ति करने की पूरी कोशिश करेंगे।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:सर, मैं माननीय मंत्री जी की योग्यता पर बहुत विश्वास रखता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि आपको कोई गलत सूचना दे नहीं सकता, आप इतने योग्य मंत्री हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आप गंभीरता से सोचें। 10,000 कम्प्यूटर 5 एनजीओज़ ने इंग्लैंड और कनाडा में इकटठे किए, पंजाब को एनआरआईज़ ने भेजने थे, 5 के लिए भी यहां आने की अनुमति नहीं मिली। मंत्री जी, आप मेरी बात पर नाराज न होना, आप दोबारा देख लें, कोई कम्प्यूटर नहीं आने देता। कम से कम आप इतना बता दें माननीय सभापति जी को या वह पेपर प्रस्तुत कर दें कि अगर यह पेपर ले जाएंगे तो आपको कोई रुकावट नहीं होगी, मैं मान जाऊंगा। आज कोई घुसने नहीं देता, दूर से ही कहते हैं कि चले जाओ यहां से, हम नहीं आने देते, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अगर कम्प्यूटर की इजाज़त दे दें तो एक साल में एक लाख कम्प्यूटर घर-घर में एनजीओज स्कूलों में आएंगे और बिहार में तो बीसियों बार आएंगे। तो मंत्री जी, आप मुझे सिर्फ़ इतना बता दीजिए कि वह कागज कौन सा है जिसे रखने से कोई रुकावट नहीं होगी?

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह व्यवस्था बहुत सरल है। हमारे मंत्रालय के पास यदि जानकारी आएगी, यदि कोई इस मामले में अपना पक्ष सामने रखेगा तो हम वित्त विभाग से उनकी मदद करेंगे। हमारे पास अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है कि किस एनजीओ ने कनाडा से कितने कम्प्यूटर कहां से इकटठे करके दिए। वह हमें एप्रोच करें, हम वित्त विभाग से इस संबंध में उनकी मदद करेंगे, लेकिन केस-बाई-केस तो उसके बारे में जरुर जांच करेंगे।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, as far as computer education is concerned, Andhra Pradesh is ranked No. 1 among all States. Sir, there

are a number of tribal areas in Araku, Visakhapatnam and other areas, where there is illiteracy. Are there any plans to give more priority to the tribal and difficult areas? I would also like to know how much amount is being allocated for computer education in Andhra Pradesh, and how much you are going to give in future.

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश के लिए 1400 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं जो कि 75% हिस्सा है, जो कि हम देते है। इसमें से 700 लाख रुपए रिलीज हो चुके हैं और करीब 500 स्कूलों में यह स्कीम चल रही है। अगर कोई राज्य अपनी स्कीम देता है तो हम उस पर फ़िर विचार करेंगे।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, is it Rs. 14 lakhs or Rs. 1400 lakhs?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: It is Rs.1400 lakhs. It comes to Rs.14 crores. You calculate it.

Explosive devices in reserve forest

*183. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether high alert has been sounded in the Jim Corbett National Park, following recovery of explosive devices in the reserve forest;

(b) if so, the number of explosive devices recovered;

(c) whether an enquiry has been held to ascertain the facts and nab the culprits; and

(d) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): (a) and (b) Yes, Sir. A total of 17 crude ball shaped explosives were recovered on 14.6.2002 from the reserved forest, which is the buffer area lying on the southern periphery of Corbett Tiger Reserve.

(c) and (d) An enquiry is being conducted in the matter and support of police has been sought. Patrolling of police has been strengthened in the Tiger Reserve.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, I am thankful to the hon. Minister that he has accepted the fact that 17 explosive devices were recovered from the Jim Corbett National Park. Sir, I would like to know what immediate action he had taken when he came to know that a country-made bomb